



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण, 1942 (श०)

संख्या- 367 राँची, शुक्रवार,

14 अगस्त, 2020 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

13 अगस्त, 2020

संख्या-एल0जी0-11/2017-327/लेज0-- झारखंड सरकार का निम्नलिखित अध्यादेश जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-10/08/2020 को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020

(झारखण्ड अध्यादेश संख्या- 02, 2020)

झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (झारखंड अधिनियम-12, 2017) में संशोधन हेतु अध्यादेश।

प्रस्तावना:-

चूंकि, झारखंड राज्य की विधान-सभा सत्र में नहीं है और चूंकि, झारखंड राज्यपाल को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण झारखंड माल और सेवा कर

अधिनियम, 2017 (झारखंड अधिनियम-12, 2017) के कतिपय विद्यमान प्रावधानों में संशोधन, विलोपन तथा प्रतिस्थापन हेतु तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है:-

इसलिए अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखंड राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश को प्रख्यापित करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ-

- (1) यह अध्यादेश झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा जाएगा।
- (2) यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा।
- (3) अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अध्यादेश के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो झारखण्ड सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे:

2. धारा 2 का संशोधन- झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें, इसके पश्चात् झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (114) में, खंड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"(ग) दादरा एवं नागर हवेली और दमण एवं दिव ;
(घ) लद्दाख;"।

3. धारा 10 का संशोधन- झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में, "किसी माल" शब्दों के पश्चात् "या सेवाओं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. धारा 16 का संशोधन- झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) में, "से संबंधित बीजक" शब्दों का लोप किया जाएगा।

5. धारा 29 का संशोधन- झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(ग) कराधेय व्यक्ति, धारा 22 या धारा 24 के अधीन अब रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं रहा है या उसका धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण का आशय रहा हो;"।

6. धारा 30 का संशोधन- झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्: -

"परंतु ऐसी अवधि दर्शित किए गए पर्याप्त कारण के आधार पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से,-

- (क) यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त द्वारा तीस दिन से अनधिक की अवधि के लिए; और

(ख) आयुक्त द्वारा, खंड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि से परे तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए; बढ़ाई जा सकेगी।”।

7. **धारा 31 का संशोधन-** झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में परंतुक शब्द के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्: -

“परंतु सरकार, परिषद् की सिफारशों पर, अधिसूचना द्वारा, -

(क) ऐसी सेवाओं या पूर्तियों के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कर बीजक जारी किया जा सकेगा;

(ख) इसमें उल्लिखित ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, सेवाओं के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में -

(i) पूर्ति के संबंध में जारी किसी अन्य दस्तावेज को कर बीजक समझा जाएगा; या

(ii) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकेगा।”।

8. **धारा 51 का संशोधन-** झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 51 में, -

(क) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्: -

“(3) स्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जारी किया जाएगा, जो विहित की जाए।”।

(ख) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा।”।

9. **धारा 122 का संशोधन-** झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

“(1क) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (vii) या खंड (ix) के अंतर्गत आने वाले संव्यवहार के फायदे का प्रतिधारण करता है और जिसके अनुरोध पर ऐसा संव्यवहार किया जाता है, अपवंचित कर या उपभोग किए गए या संक्रांत इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम की शास्ति का दायी होगा।”।

10. **धारा 132 का संशोधन-** झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) में,

(i) “जो कोई निम्नलिखित में से किसी अपराध को करता है” शब्दों के स्थान पर, “जो कोई निम्नलिखित अपराधों में से किसी अपराध को करेगा या किसी अपराध को करवाएगा और उससे उदभूत फायदों का प्रतिधारण करेगा” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट बीजक या बिल का उपयोग करके इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करता है या बीजक या बिल के बिना कपट से इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करता है ;"

(iii) उपखंड (ड.) में, "कपट से इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेता है या" शब्दों का लोप किया जाएगा।

11. धारा 140 का संशोधन- झारखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 140 में, 1 जुलाई, 2017 से, -

(क) उपधारा (1) में, "विहित की जाने वाली रीति में" शब्दों के स्थान पर "ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, "विहित की जाने वाली रीति में, शब्दों के स्थान पर "ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में" जो विहित की जाए" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जायेंगे;

(ग) उपधारा (3) में, "नियत दिन पर स्टॉक में धारित" शब्दों के स्थान पर "नियत दिन पर, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, स्टॉक में धारित" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जायेंगे;

(घ) उपधारा (5) में, "विद्यमान विधि के अधीन पूर्तिकार द्वारा" शब्दों के स्थान पर "विद्यमान विधि के अधीन ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पूर्तिकार द्वारा" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जायेंगे;

(ड) उपधारा (6) में, "नियत दिन को" शब्दों के पश्चात् "ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(च) उप-धारा (7) में, "विहित की जाने वाली रीति में" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे समय के भीतर और ऐसे रीति में, जो विहित की जाए" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जायेंगे;

12. धारा 172 का संशोधन- झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 172 में, उपधारा (1) के परंतुक में, "तीन साल" शब्दों के स्थान पर, "पांच साल" शब्द रखे जाएंगे।

13. अनुसूची II में संशोधन- झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची II की प्रविष्टि 4 में, "जो किसी प्रतिफल के लिए है या नहीं है" दोनों स्थानों पर, जहाँ वे आते हैं, शब्दों का लोप किया जाएगा और 1 जुलाई, 2017 से लोप किया गया समझा जाएगा।

14. कतिपय मामलों में राज्य कर के उदग्रहण और संग्रहण से भूतलक्षी छूट-

1. झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर झारखंड सरकार (वाणिज्य-कर

विभाग) द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या -1/2017 राज्य कर (दर) जिसे एस. ओ. सं. 31 दिनांक - 29 जून, 2017 में निहित किसी बात के होते हुए भी, -

- (i) 1 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाली और 30 सितंबर, 2019 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान (शीर्षक 2301 के अंतर्गत आने वाले) मतस्य आहार के प्रदाय के संबंध में कोई राज्य कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा;
 - (ii) 1 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाली और 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान (शीर्षक 8483 अंतर्गत आने वाली) घिर्नी, पहिए और अन्य पुर्जों के संबंध में और (शीर्षक 8432, 8433 और 8436 के अंतर्गत आने वाली) कृषि संबंधी मशीनरी के पुर्जों के उपयोग के संबंध में छह प्रतिशत की दर पर राज्य कर उद्गृहीत या संगृहीत किया जाएगा।
2. ऐसे सभी करों का कोई प्रतिदाय नहीं किया जायेगा, जिन्हें संगृहीत किया गया है किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किए गए होते, यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

13 अगस्त, 2020

संख्या-एल0जी0-11/2017-328/लेज0-- माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-10/08/2020 को अनुमत झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

JHARKHAND GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020 (Jharkhand Ordinance No. 02, 2020)

An Ordinance, to amend Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Jharkhand Act 12, 2017), in regard to its applicability and enforcement within the State of Jharkhand.

Preamble

Whereas the legislative Assembly of State of Jharkhand is not in session and whereas the Governor of Jharkhand is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action to amend and or delete and or substitute certain existing provisions and also to bring certain new provisions into the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017(Jharkhand Act No. 12, 2017).

Now, therefore, in exercise of power conferred by Clause (1) of Article 213 of Constitution of India, the Governor of Jharkhand is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. Short title and commencement -

- (1) This Ordinance may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2020.
- (2) It shall extend to the whole of State of Jharkhand.
- (3) Save as otherwise provided, the provisions of this ordinance shall come into force on such date as the Government of Jharkhand may, by notification in the Official Gazette, appoint:

2. Amendment of section 2 - In section 2 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the Jharkhand Goods and Services Tax Act), in clause (114), for clauses (c) and (d), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(c) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;

(d) Ladakh;”.

3. Amendment of section 10 - In section 10 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, in sub-section (2), in clauses (b), (c) and (d), after the words “of goods”, the words “or services” shall be inserted.

4. Amendment of section 16 - In section 16 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, in sub-section (4), the words “invoice relating to such” shall be omitted

5. Amendment of section 29 - In section 29 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, in sub-section (1), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

“(c) the taxable person is no longer liable to be registered under section 22 or section 24 or intends to opt out of the registration voluntarily made under sub-section (3) of section 25;”.

- 6. Amendment of section 30** - In section 30 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, in sub-section (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-
 “Provided that such period may, on sufficient cause being shown, and for reasons to be recorded in writing, be extended,-
- (a) by the Additional Commissioner or the Joint Commissioner, as the case may be, for a period not exceeding thirty days;
- (b) by the Commissioner, for a further period not exceeding thirty days, beyond the period specified in clause (a).”.
- 7. Amendment of section 31** - In section 31 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, in sub-section (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-
 “Provided that the Government may, on the recommendation of the Council, by notification, -
- (a) specify the categories of services or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued, within such time and in such manner as may be prescribed;
- (b) subject to the condition mentioned therein, specify the categories of services in respect of which -
- (i) any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice; or
- (ii) Tax invoice may not be issued.”.
- 8. Amendment of section 51** - In section 51 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, -
- (a) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely: -
 “(3) A certificate of tax deduction at source shall be issued in such form and in such manner as may be prescribed.”.
- (b) sub-section (4) shall be omitted.”.
- 9. Amendment in section 122** - In section 122 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:-
 “(1A) Any person who retains the benefit of a transaction covered under clauses (i), (ii), (vii) or clause (ix) of sub-section (1) and at whose instance such transaction is conducted, shall be liable to a penalty of an amount equivalent to the tax evaded or input tax credit availed of or passed on.”.
- 10. Amendment of section 132** - In section 132 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, in sub-section (1),-
- (i) for the words “Whoever commits any of the following offences”, the words “Whoever commits, or causes to commit and retain the benefits arising out of any of the following offences” shall be substituted;
- (ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: -
 “(c) avails input tax credit using the invoice or bill referred to in clause (b) or fraudulently avails input tax credit without any invoice or bill;”;
- (iii) in sub-clause (e), the words, “fraudulently avails input tax credit” shall be omitted.
- 11. Amendment of section 140** - In section 140 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, with effect from the 1st day of July, 2017, -
- (a) In sub-section (1), after the words “existing law”, the words “within such time and” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted;

- (b) in sub-section (2), after the words “appointed day”, the words “within such time and” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted;
- (c) in sub-section (3) for the words “goods held in stock on the appointed day subject to”, the words “goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as may be prescribed, subject to” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted;
- (d) in sub-section (5), for the words “existing law” the words “existing law, within such time and in such manner as may be prescribed” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted;
- (e) in sub-section (6), for the words “goods held in stock on the appointed day subject to”, the words “goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as may be prescribed, subject to” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted;
- (f) in sub-section (7), for the words “in such manner”, the words “within such time and in such manner” shall be substituted and deemed to have been substituted.

- 12. Amendment of section 172** - In section 172 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, in sub-section (1), in the proviso, for the words “three years”, the words “five years” shall be substituted.
- 13. Amendment to Schedule II** - In schedule II to the Jharkhand Goods and Services Tax Act, in paragraph 4, the words “whether or not for a consideration,” at both the places where they occur, shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st Jul, 2017.
- 14. Retrospective exemption from, or levy or collection of, state tax in certain cases -**

(1) Notwithstanding anything contained in the notification of the Government of Jharkhand (Commercial Taxes Department) Notification No. – 1/2017 State Tax(Rate) dated the 29th June, 2017, vide S.O. No. 31 Dated – 29th June 2017 issued by the Jharkhand Government, on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 9 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017, -

- (i) no state tax shall be levied or collected in respect of supply of fishmeal (falling under heading 2301), during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 30th day of September, 2019 (both days inclusive);
- (ii) state tax at the rate of six per cent. shall be levied or collected in respect of supply of pulley, wheels and other parts (falling under heading 8483) and used as parts of agricultural machinery (falling under headings 8432, 8433 and 8436), during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 31st day of December, 2018 (both days inclusive).

(2) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।
